[श्री रामावतार शास्त्री]

आप उन की बातों की तरफ ध्यान दें और उन की जायज बातों को मानें ।

SHRI R. K. KHADILKAR : I have already stated that we are thinking of bringing forward a new measure to rectify the deficiencies noticed in the working of the present Act. We shall also keep the suggestions made by my hon. friend, Mr. Damani.

There is a factual correction I want to make about figures of arrears. At the end of 1968-69 in the coal mines provident fund the amount of arrears was Rs. 4.7 crores and that comes to about 5.5 per cent. That is the only correction I wanted to make.

As I said before I shall bring forward a new comprehensive measure so that this scheme could be improved All the suggestions made here would be kept in view while bringing that Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.53 hrs.

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : Before you take up the next business, may I invite your attention to the list of business for today. The Private Member's business is relegated to the very end. The practice has been that at 3 p. m. or 3-30 p. m. the business of Private Members is taken up. Now this is a serious departure from past practice and sets a bad precedent. You should first take up Private Members' business and after giving them 2½ hours, if there is time available ; if there are Members available, then Government business might be taken up. Once a week the private Members' business gets 2½ hours, and if that is also taken up by the Government work what are we to do ? You cannot make inroads in the time of private Members' business like this. Therefore, I suggest that at 4 p.m. or 4-30 p.m. we must take up private business, and after discussing the private members' bills or resolutions for 2½ hours, you can take up Government business.

SHRI KALYANASUNDARAM (Tiruchirappali) : In addition to that there is to be a debate on a motion under rule 193. What will happen to that ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Well, I can very well appreciate the feelings of hon. Members, but there is nothing in the rules to say that Private Members' Business must be taken up at a particular time. All that the rule says is that the last two and a half hours of the sitting on Friday shall be allotted for the transaction of Private Members' Business. Therefore, that is the practice. But though today is the last day, as lot of work is there, I think it would be taken up as soon as we are able to dispose of Government business. Let us try to dispose of the business on hand as quickly as possible and then take up Private Members' Business.

15.56 hrs.

STATE OF HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE, DEPTT. OF ELECTRONICS, DEPTT. OF ATOMIC ENERGY AND DEPTT. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI K. C. PANT) : Sir, I move* :

"That the Bill to amend the State of Himachal Pradesh Act, 1970, be taken into consideration".

This is a small Bill which seeks to replace the ordinance promulgated on the 5th January, 1971. When this House passed the State of Himachal Pradesh Bill in December last, we had proceeded on the assumption that the fourth Lok Sabha would be dissolved after the new State of Himachal Pradesh would come into existence. Accordingly we had provided that six Members to the Lok

*Moved with the recommendation of the President.

Sabha elected from the union territory of Himachal Pradesh should continue to represent the new State till the dissolution of the fourth Lok Sabha. We had also provided that these Members be associated with the Election Commission in delimiting the Parliamentary and Assembly constituencies in the new State. Subsequent developments, however, belied this assumption, and we had to go in for a general election to the Lok Sabha immediately after passing of the Bill. Parliamentary constituencies had to be delimited before the election. The law had, therefore, to be changed to provide for the six persons who were Members of the dissolved Lok Sabha being associated with the Election Commission for delimiting Parliamentary constituencies. The delimitation of Assembly constituencies was to take place after the general election to the Lok Sabha. Hence we provided for the Members from Himachal Pradesh elected to the fifth Lok Sabha being associated with this work. The ordinance which was issued sought to achieve this object. This Bill merely replaces the ordinance.

Sir, I move.

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि और भी कुछ ऐसे केन्द्र प्रशासित प्रदेश हैं, उनके बारे में शासन ने क्या निर्णय लिया है ? हम चाहते हैं कि दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि राज्यों के बारे में केन्द्र शासन इसी प्रकार का शीघ्र से शीघ्र फैसला करे जिससे वहाँ के लोगों को भी राज्य का दर्जा प्राप्त होने के साथ ही साथ अन्य अधिकार एवं सुविधायें प्राप्त हो सकें।

हिमाचल प्रदेश अब तक केन्द्र शासित प्रदेश रहा है, चूंकि अब इस बिल के माध्यम से वह एक राज्य के रूप में आ जायेगा, ऐसी स्थिति में वहां पर केन्द्र शासन को एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की जरूरत है। वह यह है कि जब हिमाचल प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश था, तब वहां के कर्मचारियों को उन की मंहगाई भत्ता और वेतन केन्द्र के कर्मचारियों से अधिक मिलता था। चूंकि हिमाचल प्रदेश अब पूर्ण राज्य बन गया है, उसका अपना अस्तित्व बन गया है ऐसी स्थिति में वहां के कर्मचारियों को पहले जो मंहगाई भत्ता एवं वेतन मिलता था, उसमें किसी प्रकार की कमी न हो आशा है शासन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि केन्द्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में एक ऐसी प्रणाली केन्द्र को लागू करनी चाहिये, जिससे अन्य राज्यों को जब उन्हें हम पूरे राज्य का दर्जा दें तो उसका ध्यान रखा जाय। इससे लाभ यह होगा कि राज्यों का निर्माण करते समय एक रूपता आयेगी और शासन के सामने जो कठिनाइयां आती है, उससे शासन को छुटकारा मिलेगा।

16.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आज की परिस्थितियों में यह बात जरूरी हो गई है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाय। दिल्ली के नागरिकों की अपनी एक विशेष समस्या है और उसको दूर करना शासन का परम कर्त्तव्य है। खुशी की बात है कि इंदिरा जी की कांग्रेस के लोग दिल्ली की सातों सीटों पर विजयी हुए हैं। इंदिरा जी की कांग्रेस ने वोट मांगते समय दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था कि यदि यहां से कांग्रेस सातों सीटों पर विजयी रही तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। आज मैं उस बात को याद दिलाते हुए सत्तारूढ दल के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके दल ने जनता को जो आश्वासन दिया है, उस को आप पूरा करें अन्यथा दिल्ली की जनता जन आन्दोलन के लिए मजबूर हो जायेगी और

[श्री फूलचन्द वर्मा]

फिर स्थान स्थान पर आन्दोलन होने पर यहां कानून और व्यवस्था की समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक देखने में आया है कि जितने भी नये राज्यों का निर्माण किया गया है उनके निर्माण में राजनीतिक कारणों को अधिक महत्व दिया गया है बजाये इसके कि उन राज्यों की अपनी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप किसी राज्य का निर्माण करने की बात करें तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है और वहां उद्योग धंधों के क्या चांसेज हैं। ऐसी सभी बातों पर आप का ध्यान जाना चाहिये और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि वहां के लोगों जैसे हरिजन, आदिवासी, व्यापारी बंधु आदि की क्या समस्यायें हैं। यदि इन सारी बातों को ध्यान में रख कर किसी राज्य का निर्माण किया जायेगा तो उसमें सफलता मिलेगी अन्यथा यदि पोलिटिकल प्रेशर्स के कारण आप राज्यों का निर्माण करेंगे तो राज्य तो अधिक होते जायेंगे और नई-नई समस्यायें पैदा होंगी। तेलंगाना वाले नये राज्य की मांग कर रहे हैं, डी०एम०के० वाले बंगला देश की दुहाई देकर अलग राज्य की बात करते हैं, इस प्रकार की तमाम समस्यायें आपके सामने आयेंगी।

अन्त में मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली की समस्याओं को नजरन्दाज न करे, दिल्ली के लोगों ने आप के दल को पूरा-पूरा सहयोग दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने विचाराधीन है उसको राष्ट्रपति जी आर्डिनेंस के द्वारा 5 जनवरी, 1971 को अमल में लाये थे और वह एक बहुत अच्छा कदम था। असल में धारा 8 और 9 में यह दर्ज था, कि स्टेट बनने से पहले जो 6 मेम्बर लोक सभा में नुमाइंदगी करते हैं वे चौथी लोक सभा की अवधि तक मेम्बर बने रहेंगे। इसी तरह से धारा 17 (2) (ए) में तयशुदा बात थी कि वे मेम्बर डिलिमिटेशन कमीशन के असोशिएटेड मेम्बर होंगे। लेकिन अचानक हालात में तब्दीली आई और निर्धारित समय से पहले ही लोक सभा भंग करनी पड़ी। इस प्रकार जो प्रोटेक्शन धारा 8 और 9 तथा 17 (2) (ए) में दी गई थी वह अमल में लाई नहीं जा सकती थी क्योंकि लोक सभा भंग हो जाने के बाद उसूलन हिमाचल प्रदेश के 6 मेम्बरों की बजाये 4 मेम्बर मुन्तखिब होने थे। उस बात की पूर्ति के लिये प्रेसीडेन्ट महोदय ने आर्डिनेंस निकाला और वही बिल के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहता हूं कि इस थोड़े से समय में उसने बहुत ठीक तरह से पार्लिमेंट्री कांस्टीट्रएंसीज का बाईफर्केशन किया जिसमें किसी को भी कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिला। आगे चल कर असेम्बली कांस्टीटुएन्सीज भी बजाये 60 के 63 होनी हैं। इस लिये अब यह लाजमी हो जाता है कि एलेक्शन कमीशन इस कार्य को बहुत जल्दी अपने हाथ में ले क्योंकि आगामी चुनावों में अब केवल 1. महीने ही रह गये हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी इस कार्य को अपने हाथ में ले ताकि पार्टियों को और वहां के नुमाइंदों को पूरा पूरा मौका मिल सके जो कि पहली दफा नहीं मिल सका कि लोग अपने ख्यालात और सुझाव कमीशन के सामने रख सकते और कमीशन ठीक ढंग से लागू कर सकता। इस लिये मेरा निवेदन है कि अब इसमें जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिल सके।

मुझे एक बात और निवेदन करनी है। इस चुनाव में एलेक्टोरल रोल्ज में बहुत खराबियां थी जैसे कि किसी मुर्दा आदमी को तो जिन्दा दिखा दिया गया और जिन्दा आदमी को मुर्दा दिखा दिया गया और बहुत सारे कुन्बे तो साफ ही हो गए। तो इस किस्म की बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और उसका कारण यह था कि एलेक्टोरल रोल्ज बहुत पुराने बने हुए हैं जिस में कि पटवारियों ने घर पर या दफ्तर में बैठ कर खानापुरी कर दी।...(व्यवधान)...इसी प्रकार से उसमें बहुत से आल्ट्रेशंस और एडीशंस भी किये गये हैं। इस लिए मेरा सुझाव हैं कि आगामी चुनावों से पहले एलेक्टोलर रोल में तब्दीलियां की जायें। उसको बनाने का सबसे अच्छा आधार पंचायतें हो सकती हैं क्योंकि पंचायतों के पास पूरे रिकार्ड मौजूद हैं। पंचायतें छोटी छोटी होती हैं इस लिये पंचायतों के आधार पर ही एलेक्टोलर रोल बनें और नये सिरे से उनको बनाया जाये ताकि नये चुनाव में किसी को कोई शिकायत या दिक्कत न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यावाद देता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूँ।

SHRI NARAIN CHAND (Hamirpur) : Sir, I rise to congratulate the Central Government for granting full statehood to the State of Himachal Pradesh. But may I bring to the notice of the House that though the State of Himachal Pradesh has come to stay, it is not complete at all in the sense that many of the hilly areas, which are linguistically akin to Himachal Pradesh and Kangra are not at present in Himachal Predesh ? There has been a reference here that the Central Government is thinking of appointing a boundary commission to settle the linguistic dispute among Himachal Pradesh, Punjab and Haryana. I would request the Central Government that justice should be done to Himachal Pradesh so that Himachal Pradesh can be completed in shape and size and Kalka, Nangal, Mukerian and Pathankot some of which were formerly parts of Kangra District should be merged with Himachal Pradesh.

Then I want to bring to your notice some of the urgent problems we are facing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This Bill is very limited in its scope. It relates only to the delimitation of constituencies. There would be other occasions with the hon. Member can present his problems.

SHRI NARAIN CHAND : I want this dispute to be settled for all time to come so that we are not pulled down by economic problems which are at present arising on account of the left-out areas. Now the railway line stops a few miles away at Nangal and so also in Pathankot, with the result that there are no broad-guage railway lines in Himachal Pradesh. For the present the railway line should be extended to Una and finally Nangal and other rail heads should form part of Himachal Pradesh so that both economic and linguistic problems could be solved.

Then there is a great demand for a sainik school in Himachal Pradesh because it is a defence area. It is an urgent need of the hour.

Finally, I welcome the Bill and wish prosperity to my State. I also congratulate the Central Government and the Members of Parliament who were here in the past and who were not here now, for their co-operation and good-wishes to us.

SHRI K. C. PANT : Sir, as you mentioned more than once, the object of this Bill is very limited. It is not a Bill which is creating the State of Himachal Pradesh. Many hon. Members will remember with great joy that we have passed that Bill during the life of the last Parliament. The limited object of this Bill has been spelt out in my opening speech and in the Statement of Objects and Reasons. My hon. friend, Shri Pratap Singh, has also referred to the object of the Bill. I need not repeat them.

During the course of the debate a few matters were raised which did not fall within the purview of the Bill. Sir, if you will permit me, I shall say just a few words about them. Firstly, there was a reference to some other territories like Manipur, Tripura and Meghalaya. We are considering that question and we have often come be-

[Shri K. C. Pant]

fore the House and explained that we shall have to take a co-ordinated and integrated view of the needs of security and development of the whole of the north-eastern region of this country.

Certain proposals have been formulated and these are under consideration. After that, we shall naturally becoming before this House with necessary legislation.

So far as Delhi is concerned, I need not repeat the argument. We have had many debates in this House. But I would accept the advice of my hon. friend in one respect when he said that we should not yield to political pressure in the matter of creation of new States and that we should take into account factors like economic viability, population and so on. He referred to the fact that if for Delhi no Statehood is granted, then there will be an agitation and the law and order problem will deteriorate. I am taking his advice and I can tell him that such threats will not make us change our mind.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Friendly warning.

SHRI K. C. PANT : Even friendly pressures will not be taken into account.

श्री फूलचन्द वर्मा : चुनाव के समय जो वायदे किये थे वह याद दिलाना चाहते हैं ।

SHRI K. C. PANT : I do not think my hon. friend is right in saying that we made any such electoral promise. In fact, I have had occasion to come before this House several times in the past to say that Delhi will not be made a State. I do not think that is quite correct. But if he has heard it from somebody, I am willing to listen to him and if he lets me know about it, I will enquire from my party why they had said so.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to amend the State of Himachal Pradesh Act, 1970, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments at all. So, I put all the clauses together.

The question is :

"That clauses 2 to 4 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.13 hrs.

MOTION *RE.* CONDUCT OF MEMBER DURING PRESIDENT'S ADDRESS

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : I beg to move :

"That this House strongly disapproves of the conduct of Shri Ram Deo Singh who created obstruction and showed disrespect to the President on the solemn occasion of his Address to both the Houses of Parliament assembled together under article 87 of the Constitution on the 23rd March, 1971 and condemns his undesirable, undignified and unbecoming behaviour."

Sir, I am not very happy when I bring this Motion before the House for the simple reason that the hon. colleague is an hon. Member of this House and I also know that he is a new Member of this House. But at the same time, it is my duty to point out and bring to the notice of this House the misbehaviour of the hon. Member on the 23rd March when the President was addressing both the Houses of Parliament in a joint session which met in the Central Hall of this Parliament House.

On that day, the President was discharging his constitutional responsibility,